भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3760
गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक)

कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और अल्परोजगार

3760 # श्रीमती दर्शना सिंह:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और अल्परोजगार की वर्तमान राज्य-वार दर कितनी है; और
(ख) कृषि में अल्परोजगार की समस्या से निपटने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में कौन सा बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। साथ ही, वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य के आधार स्थिति में 46.1% श्रमिक कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जुड़े हुए हैं।

क्षेत्रवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं और इन्हें https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

केंद्रीय बजट (2025-26) में कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके कृषि में अल्प रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन' कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर सृजित करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता को उत्प्रेरित करना है; युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार और व्यवसायों के सृजन में तेजी लाना है।